



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 06, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2026)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

मखाना उत्पादन की बढ़ती हुई मांग के साथ अवसर और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन

*डॉ. सुनील कुमार मंडल

सहायक प्राध्यापक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, झंझारपुर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,
पूसा, समस्तीपुर, बिहार, भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: skmandal6464@gmail.com

मखाना की खेती बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देने वाली बन गई है, खासकर मिथिलांचल और कोसी सीमांचल क्षेत्रों में, जहाँ हमारे देश के मखाना उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा होता है। अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर और खनिज पदार्थों के लिए मशहूर, मखाना की मांग देश और विदेश दोनों जगह बढ़ रही है, क्योंकि इसके स्वास्थ्य फायदे होते हैं। राष्ट्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने मखाना के विकास के लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया है। भारत सरकार ने बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना 2022 में की है। इस पहल का मकसद अनुसंधान को सहायता करके, प्रसंस्करण का आधारभूत संरचना को विकसित करने के साथ बाजार तक पहुँच बढ़ाकर इस सेक्टर को मजबूत करना है। मुख्य उपयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और टिकाऊ गतिविधियों को अपनाना शामिल है।

जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने, बीज की गुणवत्ता को सुधारने और आधुनिक तकनीकी को अपनाने पर ध्यान देने से उद्योग और मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार के मजबूत समर्थन से बिहार का मखाना उद्योग काफी बढ़ने वाला है, जिससे किसानों को आय के ज्यादा मौके मिलेंगे और राज्य इस पौष्टिक सुरपफूड के उत्पादन में अन्तराष्ट्रीय बाजार बनेगा।

मखाना की खेती बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, जो हजारों छोटे-किसानों को रोजी-रोटी देती है। खेती के पारम्परिक तरीके, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनमें तालाबों में बीज बोना, पानी के स्तर का कुशल प्रबंध करना और कई महीनों (8-9 महीना) के बाद मखाना फसल की कटाई करना शामिल है। यह प्रक्रिया मेहनत वाला है, जिसमें किसानों को बीज एकत्रित करने के लिए कीचड़ वाले पानी से गुजरना पड़ता है, जिन्हें फिर साफ किया जाता है, धुप में 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है और भूना जाता है।

आर्थिक रूप से मखाना एक फायदेमंद फसल के रूप में उभरा है, खासकर स्वस्थ भोजन की बढ़ती मांग के साथ। खेती के अतिरिक्त, इस फसल ने प्रसंस्करण, पैकिंग और वितरण पर केन्द्रीत करने वाले क्षेत्रीय उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अलग-अलग अन्तराष्ट्रीय बाजारों में मखाना का निर्यात राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है।

इसके महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मखाना क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पहल की है, जिसमें मखाना सहकारी समिति की स्थापना भी शामिल है।

मखाना की खेती न सिर्फ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को गुजारा देती है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान देती है, जो इस क्षेत्रों के खेती-बाड़ी के माहौल में मखाना फसल की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

मखाना बोर्ड की भूमिका

बिहार के लिए एक निर्णायक परिवर्तनकारी (गेम-चेंजर) है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होना राज्य के खेती-बाड़ी के क्षेत्र में एक बड़ी तरक्की है, खासकर मखाना की खेती करने वाले गाँवों के किसानों को इससे फायदा होगा। राष्ट्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस पहल का मकसद मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन पहल को बढ़ाना है, जिससे रोजी-रोटी बेहतर होगी और बिहार की इस सुपरफूड उद्योगों में ग्लोबल लीडर बनेगा।

मखाना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य

■ **अनुसंधान और विकास :** बोर्ड अधिक पैदावार वाली और बीमारियों से बचाने वाली मखाना की किस्मों का विकास के लिए अनुसंधान में निवेश करेगा, जिससे उत्पादकता और स्थाईत्वता बढ़ेगी।

■ **कटाई के बाद प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना :** कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाई और भण्डारण की सुविधाएं पर ध्यान दिया जायेगा।

बाजार तक पहुँच और संवर्धन : घरेलू और अन्तराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच आसान बनाकर, बोर्ड का मकसद निर्यात को बढ़ावा देना और बिहार के मखाना की अन्तराष्ट्रीय पहचान को बढ़ाना है।

किसान कल्याण : इन पहलों में किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) में संगठित करना, प्रशिक्षण देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग

बोर्ड बिहार के उत्पादित मखाना को एक प्रिमियम प्रोडक्ट (सर्वश्रेष्ठ उत्पाद) के तौर पर ब्रांडिंग करने पर काम करेगा और इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जी.आई.) टैग अर्थात् भौगोलिक संकेत लेबल का इस्तेमाल करके इसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में अलग पहचान दिलायेगा। इन कोशिशों को पूरा करते हुए, सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट की स्थापना का भी घोषणा किया है। यह संस्थान उत्पाद का प्रसंस्करण करने में मदद भी करेगा। इन खास कोशिशों से, बिहार का मखाना सेक्टर बेहतर विकास के लिए तैयार है, जिससे किसानों के अधिकतम आय का मौका मिलेगा और अन्तराष्ट्रीय सुपरफूड मार्केट में राज्य की जगह मजबूत होगी।

बिहार में मखाना की खेती में चुनौतियाँ और मखाना बोर्ड की भूमिका

अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद, मखाना उद्योग बिहार के लिए कई बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसका समाधान करके उसका सम्पूर्ण विकास की उम्मीदों को पूरा किया जाना चाहिए :

पानी के प्रबंधन में दिक्कत/बाधाएँ : मखाना की खेती, जल स्तर के स्थिर रहने पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जो अक्सर अनियमित वर्षा और सिंचाई के खराब पद्धति के कारण रूक जाता है। किसानों को अक्सर पानी की सही हालत बनाये रखने में मुश्किलें आती हैं। पानी के प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की कोशिशों से इन दिक्कतों के कम होने की उम्मीद है।

आधुनिक प्रसंस्करण इकाई की कमी : बिहार में आधुनिक मखाना प्रसंस्करण की सुविधाओं की कमी है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बहुत कम होता है और कटाई के बाद काफी नुकसान होता है। कई किसानों के पास अच्छी तरह से सुखाने और भूनने की तकनीकी ज्ञान नहीं है, जो उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जरूरी है। इस चुनौती से निपटने के लिए मखाना बोर्ड के द्वारा आधुनिक प्रसंस्करण की आधारभूत संरचना में निवेश जरूरी है।

तकनीकों का कम इस्तेमाल : बिहार में मखाना की खेती का तरीका काफी हद तक पारम्परिक है। बहुत से किसानों के पास खेती के नये औजार या जानकारी नहीं हैं। मखाना बोर्ड इस कमी को पूरा करने के लिए जागरूकता और खेती की नई तकनीकों तक पहुँच को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पैदावार और फसल की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

बाजार में अस्थिर पहुँच और कीमत में उतार-चढ़ाव : बढ़ती मांग के बावजूद, किसानों को अक्सर भरोसेमंद बाजार तक पहुँचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और विचौलियों के द्वारा भोशन का शिकार होने का खतरा रहता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मखाना बोर्ड सीधे बाजार लिंक को मजबूत करने और बिहार के मखाना को एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज के लिए सही और स्थिर कीमत मिल सके।

नये बजट की घोषणा का प्रभाव : 2025 के यूनियन बजट में खेती-बाड़ी के क्षेत्रों (सेक्टरों) की तरक्की पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें बिहार के मखाना किसानों की सहायता करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में कई ऐसे कदम बताए गए हैं जिनसे इस सेक्टर पर अच्छा असर पड़ने की उम्मीद है।

मखाना बोर्ड का गठन : सरकार ने खेती के बजट का एक बड़ा हिस्सा मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए दिया है, जो मखाना उद्योग के बड़े पैमाने पर विकास पर ध्यान देगा। यह बोर्ड एक विनियमन और विकास प्राधिकरण के तौर पर कार्य करेगा, जो उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात की गतिविधियों की देखरेख करेगा। यह गुणवत्ता मापदंड (क्वालिटी स्टैंडर्ड) का पालन सुनिश्चित करेगा और किसानों को उनका मुनाफा बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय-समय पर कार्यान्वित करेगा और मखाना में जैविक खेती की तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता : आधारभूत संरचना का एक बड़ा हिस्सा मखाना की खेती को सहायता करने वाले आधुनिक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दिया गया है। इसमें प्रसंस्करण इकाई, भण्डारण सुविधा, और कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) चैन बनाना शामिल है, जिन्हे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्नैक्स, भुने हुए बीज और पाउडर जैसे मखाना से बने अलग-अलग उत्पादों को बनाने के लिए वैल्यू-एडेड प्रोसेसिंग यूनिट (मूल्यसंवर्धित प्रसंस्करण इकाई) लगाने में भी काफी निवेश किया जायेगा। इस आधारभूत संरचना को बढ़ाने का मकसद किसानों को अपनी फसलों की कीमत बढ़ाने और इस तरह उनकी आय की वृद्धि में सहायता करना है।

मखाना की खेती के लिए अनुसंधान और विकास : बजट में बीज की गुणवत्ता, फसल की अच्छी पैदावार और कीटों व बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने वाली अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रावधान शामिल है। मखाना बोर्ड खेती की बेहतर तकनीकों, कीट व बीमारियों के लिए बेहतर रणनीतियाँ और बेहतर जल प्रबंधन के तरीकों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग की कोशिशों भी मखाना फसलों को जलवायु परिवर्तन और दुसरे पर्यावरणीय प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

मखाना निर्यात को बढ़ावा : भारत सरकार स्वस्थ भोजन और सुपरफूड्स की बढ़ती अन्तराष्ट्रीय मांग को मानती है और इस श्रेणी (कैटेगरी) में मखाना लोकप्रिय हो रहा है। विशेष आवंटित बजट निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति के हिस्से के तौर पर मखाना बोर्ड एक्सपोर्ट-फ्रेंडली पॉलिसी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अधिक बेहतर बनाने के

लिए कदम उठायेगा। सरकार किसानों को अन्तराष्ट्रीय पैमाने (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स) को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे अन्तराष्ट्रीय बाजार में बिहार के मखाना की मौजूदगी बढ़ेगी।

किसानों की भलाई और वित्तीय सहायता : मखाना बोर्ड के लिए बजट का एक आवक भाग किसानों की भलाई को बढ़ाना है। बीज, उर्वरक और सिंचाई (पानी की प्रबंधन के उपकरण) जैसे जरूरी इनपुट/निवेश के लिए वित्तीय अनुदान (सब्सिडी) दी जायेगी, जिससे किसान ज्यादा बेहतर और आधुनिक खेती के तरीके अपना सकेंगे। इसके अलावा बाढ़ या सूखे जैसी अचानक होने वाली घटनाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए इश्योरेंस स्कीम (बीमा योजना) शुरू की जायेगी। मखाना बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की तकनीकी जानकारी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी।

बिहार के मखाना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग : मखाना को एक सर्वश्रेष्ठ उत्पाद (प्रीमियम प्रोडक्ट) के तौर पर ब्रांडिंग करने और बाजार करने के लिए संसाधन दिये गये हैं। सरकार का मकसद बिहार के मखाना को एक ऑर्गेनिक, उच्च गुणवत्ता की उत्पाद के तौर पर बनाना है, जो दुनिया भर के खरीदारों को पसन्द आये। बोर्ड मखाना के पोषण (न्यूट्रिशनल) फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे एक स्वस्थ पर्यावरण के अनुकूल स्नैक के तौर पर प्रोत्साहन करने के लिए एकीकृत ब्रांडिंग की रणनीति का विकास करेगा। इस विपणन पहल (मार्केटिंग इनिशिएटिव) से किसानों को देश और विदेश में अपनी बिक्री बढ़ाने के नये अवसर मिलने की उम्मीद है।

टिकाऊ और जैविक खेती के तरीके : बजट में मखाना जैसी फसलों के लिए टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि मखाना प्राकृतिक रूप से एक जैविक (आर्गेनिक) फसल है। इसलिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को बढ़ाने और इसे एक प्राकृतिक, पर्यावरण हितैषी उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मखाना बोर्ड आर्गेनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने और किसानों को आर्गेनिक प्रमाणिकरण प्रमाण-पत्र दिलाने में मदद करने के लिए काम करेगा, जिससे सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जैविक भोजन (प्रीमियम ऑर्गेनिक फूड) बाजार में आ सके।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोधी खेती के तरीके : जलवायु परिवर्तन से खेती को होने वाले बड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए, बजट में जलवायु प्रत्यास्थ खेती के तरीके बदलने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मखाना बोर्ड विशेषज्ञ/वैज्ञानिक के साथ मिलकर किसानों को बदलते मौसम के स्वरूप (पैटर्न) के आंकलन से ढलने में मदद करने के लिए रणनीतियां बनायेगा, जिसमें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (जल संचयन), सिंचाई के बेहतर तकनीके और सुखा-सहिष्णु फसल की किस्में शामिल हैं। इन प्रयासों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खराब मौसम के बावजूद मखाना की खेती टिकाऊ (सस्टेनेबल) और लाभकारी बनी रहे।

निष्कर्ष

मखाना की उन्नत खेती से बिहार की खेती-बाड़ी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस पौष्टिक सुपरफूड के शीर्ष उत्पादक के तौर पर राज्य के पास बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और वैश्विक खाद्य बाजारों में अपनी जगह मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है। मखाना बोर्ड की स्थापना से खेती और प्रसंस्करण से लेकर निर्यात तक मखाने का सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला एक हो जायेगी, जिससे एक लाभ मजबूत और टिकाऊ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस विकास से किसानों की रोजी-रोटी बेहतर होगी और साथ ही बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान होगा। सरकार के लगातार मदद से बिहार का मखाना घरेलू और अन्तराष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक स्वस्थ उत्पाद के तौर पर पहचान बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य आने वाले कई वर्षों तक इस बढ़ते हुए क्षेत्र में अग्रणी भूमिका बनाए रख सकेंगे।